

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	ज्येष्ठ 10, शुक्रवार, शाके 1946-मई 31, 2024 <i>Jyaistha 10, Friday, Saka 1946- May 31, 2024</i>	

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।**

**वन विभाग**

**विज्ञप्ति**

**जयपुर, अप्रेल 03, 2024**

**संख्या प. 2(15)वन/2024** :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध ही किये गये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों

को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,  
विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)  
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची										
क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा		खसरा नंबर	विवरण			
				दिशा	भूमि		नाम ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (बीघा में )	क्षेत्रफल (है० में)
1.	रक्षित वनखंड खेरखेडा	अकलेरा	झालावाड़	पूर्व	गैर मूमकिन रस्ता	130/3	खेरखेडा	1	19 बीघा 07 बिस्वा	4.8967
				पश्चिम	वन भूमि वनखंड नैश	86/1		2	03 बिस्वा	0.0405
				उत्तर	सीमा ग्राम चंद्रपुरिया	-				
				दक्षिण	सीमा ग्राम किशोरपुरा बडिया	-				
कुल योग वनखंड खेरखेडा :-									19 बीघा 10 बिस्वा	4.9372

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अकलेरा

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
झालावाड़

## द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड खेरखेडा

## पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Diospyros Melanoxylon roxb	तेन्दू
2	Nyctanthes arbortristis	रोंज
3	Azadirachta indica	नीम
4	Vachellia nilotica	बबूल
5	Prosopis cineraria	खैजड़ी
6	Holoptelea integrifolia	चुरेल

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अकलेरा

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
झालावाड़

## कार्यालय उप वन संरक्षक झालावाड़

प्रमाण पत्र

जिला :- झालावाड़  
तहसील :- अकलेरा  
रेंज :- अकलेरा  
रक्षित वनखण्ड :- खेरखेडा  
ग्राम :- खेरखेडा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण छापी सिचाई परियोजना के विरुद्ध प्राप्त गैर वनभूमि है जिसको वन विभाग के नाम अमल-दरामद की जा चुकी है। भूमि की किस्म गे.मु0 जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यों के कराये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न हैं जिस में खसरा नं. व रकबा दर्ज है।
5. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कारण रहे हैं। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक हैं। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
6. इस भूमि का पूर्व में राज पत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अकलेरा

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
झालावाड़

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।